



Publication	Deccan Chronicle	Language	English
Edition	Chennai	Journalist	PTI
Date	20/08/2023	Page no	4
CCM	20.06		

NEW NATIONAL COOP POLICY READY: PRABHU

NEW NATIONAL COOP POLICY READY: PRABHU

Kolkata: The new National Cooperative Policy is almost ready, and a 47-member committee is in the process of submitting the draft to the Central government, chairman of the panel and former Union minister Suresh Prabhu said. Union home and cooperation minister Amit Shah had last year announced that a dedicated policy will soon be prepared to strengthen the cooperative movement in the country, and that Mr Prabhu will head the national-level



committee. The panel members include experts and representatives of the cooperative sector and officials of Central ministries. "The policy document is almost ready and the submission process is underway. We can now look forward to the release of the policy and its implementation," Mr Prabhu said on the sidelines of an event organised by the Merchants' Chamber of Commerce & Industry here. The former commerce and industry minister said the policy has the potential to change the socio-economic dimension of India, substantially increasing the share of cooperatives in the total GDP. Mr Prabhu said the idea behind the policy is to promote a economic development model backed by a legal and institutional framework. — PTI



Publication	The Pioneer	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	PTI
Date	20/08/2023	Page no	6
CCM	18.60		

New National Cooperative Policy almost ready: Suresh



New National Cooperative Policy almost ready: Suresh

PTI ■ KOLKATA

The new National Cooperative Policy is almost ready, and a 47-member committee is in the process of submitting the draft to the central government, chairman of the panel and former Union minister Suresh Prabhu said.

Union Home and Cooperation Minister Amit Shah had last year announced that a dedicated policy will soon be prepared to strengthen the cooperative movement in the country, and that Prabhu will head the national-level committee.

The panel members include experts and representatives of the cooperative sector and officials of central ministries.

"The policy document is almost ready and the submission process is underway. We can now look forward to the release of the policy and its implementation," Prabhu told PTI on the sidelines of an event organised by the Merchants' Chamber of Commerce & Industry here.



Publication	Millennium Post	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	PTI
Date	20/08/2023	Page no	2
CCM	15.91		

'New National Cooperative Policy almost ready'

'New National Cooperative Policy almost ready'

KOLKATA: The new National Cooperative Policy is almost ready, and a 47-member committee is in the process of submitting the draft to the central government, chairman of the panel and former Union Minister Suresh Prabhu said. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah had last year announced that a dedicated policy will soon be prepared to strengthen the cooperative movement in the country, and that Prabhu will head the national-level committee. The panel members include experts and representatives of the cooperative sector and officials of central ministries.

"The policy document is almost ready and the submission process is underway. We can now look forward to the release of the policy and its implementation," Prabhu said on the sidelines of an event organised by the Merchants' Chamber of Commerce & Industry here. Prabhu said the idea behind the policy is to promote a cooperative-based economic development model backed by a legal and institutional framework.

PTI

Publication	Punjab Kesri	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	20/08/2023	Page no	9
CCM	15.24		

New National Cooperative Policy ready : Suresh Prabhu

नई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार : सुरेश प्रभु

कोलकाता, (पंजाब केसरी):

नई राष्ट्रीय सहकारी नीति लगभग तैयार हो चुकी है और 47 सदस्यीय समिति इसे केंद्र सरकार के पास भेजने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है।

समिति के चेयरमैन और पूर्व



केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले साल घोषणा की थी कि देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए जल्द ही एक इसी के लिए एक नीति तैयार की जाएगी। इसकी राष्ट्रीय स्तर की समिति की अध्यक्षता सुरेश प्रभु करेंगे। समिति के सदस्यों में सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं। प्रभु ने यहां मर्चेन्ट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर कहा, “नीति दस्तावेज लगभग तैयार है और इसे दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है।



Publication
Edition
Date
CCM

Rashtriya Sahara
New Delhi
20/08/2023
36.51

Language
Journalist
Page no

Hindi
PTI
7

New National Cooperative Policy is ready: Suresh Prabhu

तैयार है नई राष्ट्रीय सहकारी नीति : सुरेश प्रभु

टकोलकाता (भाषा)। नई राष्ट्रीय सहकारी नीति लगभग तैयार हो चुकी है और 47 सदस्यीय समिति इसे केंद्र सरकार के पास भेजने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। समिति के चेयरमैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने यह जानकारी दी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले साल घोषणा की थी कि देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए जल्द ही एक इसी के लिए एक नीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा था कि इसकी राष्ट्रीय स्तर की समिति की अध्यक्षता सुरेश प्रभु करेंगे। समिति के सदस्यों में सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं।

प्रभु ने यहां मर्चेन्ट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर कहा, 'नीति दस्तावेज लगभग तैयार है और इसे

दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। हम अब नीति जारी होने और इसके लागू होने की उम्मीद कर सकते हैं।'

पूर्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि नीति में भारत के सामाजिक-आर्थिक

**समिति के सदस्यों में
सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ
और प्रतिनिधि के साथ
केंद्रीय मंत्रालयों के
अधिकारी शामिल**

आयाम को बदलने की क्षमता है, जिससे कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि होगी।

प्रभु ने कहा कि नीति के पीछे का विचार कानूनी और संस्थागत ढांचे द्वारा समर्थित सहकारी-आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'मैं लंबे समय से सभी प्रकार की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ हूँ और उनकी क्षमता जानता हूँ। कोई भी आर्थिक गतिविधि लोगों के जीवन में मूल्य बढ़ाएगी, लेकिन सहकारी समितियां धन पैदा करने के साथ-साथ आय फैलाने और वितरित करने में भी मदद करती हैं।'

उन्होंने कहा, 'यही कारण है कि सरकार अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के बारे में सोच रही है।' सहकारी समितियों पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति 2002 में बनाई गई थी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जिनका सदस्य आधार लगभग 29 करोड़ है। ये सहकारी समितियां कृषि-प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, आवास, बुनाई, ऋण और विपणन जैसी विभिन्न गतिविधियों में लगी हुई हैं।